राष्ट्रीयकृत बैंकों के बट्टे खाते

776. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये कर्ज की राशि में से कितनी राशि बट्टे खाते में डाली गई है; और

(ख) किन-किन व्यक्तियों अथवा कम्पनियों का 10 करोड़ रुपये अथवा अधिक का कर्ज बट्टे खाते में डाला गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबी प्रसाद पाल): (क) विवेकसम्मत मानदण्डों के अनुसार अनुपयोज्य आस्तियों (एन पी ए) को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है अर्थात् अवमानक, संदिग्ध और हानि वाली आस्तियां। "अशोध्य ऋण खाता" जैसा कोई वर्गीकरण नहीं है। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31.3.95 तक एन पी ए की कुल राशि 25114.50 करोड़ रुपए थी।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनकी आंकड़ा सूचना प्रणाली से व्यक्तिगत ऋण खातों से संबंधित सूचना प्राप्त नहीं होती है।

Doordarshan's Programme to Raise Resources

777. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Doordarshan has a programme to raise its resources;

(b) if so, the target set by Doordarshan therefor; and

(c) the aims and objectives for raising resources?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI P.M. SAYEED): (a) Yes, Sir. It is the constant endeavour of Doordarshan to augment its commercial revenue.

(b) The estimated commercial revenue targets of Doordarshan are:—

	(Rs. in crores)
1995-96	455
1996-97	520
1997-98	600

(c) In order to bring about an improvement in the quality of the content and reach of Doordarshan's programmes and network respectively.

Conveyance Allowance to Central Government Employees

778. SHRI RAJ NATH SINGH:
SHRIMATI MALTI SHARMA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Government propose to provide conveyance allowance to the Central Government Employees working in metropolitan cities;

(b) if so, the detail thereof; and

(c) by when the said facility is likely to be provided?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) No, Sir.

(b) and (c) Does not arise.

प्रत्यक्ष करों के मामलों में वृद्धि

779. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री नागमणि:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्यक्ष करों से संबंधित मामलों में निरंतर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान हेतु एक राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर प्राधिकरण अथवा न्यायालय गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और